



खबर संक्षेप

सड़क हादसे में घायल डीपीओ राठौर की इलाज के दौरान मौत बालोद। जिले में पूर्व में पदस्थ रहे जिला महिला एवं बाल विकास



अधिकारी हरिकीर्तन राठौर सड़क हादसे में घायल हुए थे। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तीन दिनों पहले ही जिले के नेशनल हाईवे -30 में पुरु थाना क्षेत्र के मरकाटोला घाट के पास तेज रफ्तार यात्री बस ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में जिले के तत्कालीन महिला एवं बाल विकास अधिकारी हरिकीर्तन राठौर भी गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। जानकारों के अनुसार मृतक हरिकीर्तन राठौर की पसली कई जगहों से टूट गई थी। रायपुर के निजी अस्पताल में शुरुवार को उनकी मौत हो गई। हरिकीर्तन राठौर वर्तमान में कांग्रेस जिले में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी के पद पर पदस्थ थे।

डेंगू व जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करने हुई बैठक

बालोद। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार जिले में डेंगू एवं अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज बीएसपी अस्पताल दल्लौराजहरा में डेंगू के नियंत्रण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय एवं स्थानीय शासकीय, निजी चिकित्सालय के संचालक चिकित्सकों तथा पेशोलांजी केंद्र के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डेंगू मरीजों के प्रबंधन जांच एवं इसके रोकथाम के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में डेंगू के रोकथाम के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु बीएसपी प्रबंधन नगर पालिका परिषद और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर लावार्वा नाशी दवा छिड़काव, फर्गिंग के साथ साथ घर-घर सर्वेक्षण करते हुए खेत नियंत्रण अन्तर्गत कूलरोस की गमलो टूटे-फूटे पात्रों आदि की सफाई आदि के संबंध में कार्ययोजना तैयार की गई।

चारभाटा मुक्तिधाम में किया गया पौधारोपण

बालोद/सिकोसा। ग्राम चारभाटा में प्रेमलाल साहू और नहावन के कार्यक्रम में उनके परिवार द्वारा मुक्तिधाम में पीपल, बरगद एवं बेल का पौधारोपण किया गया। जिसमें गांव के नागरिक भिखारी राम, टीकाराम, डोमन लाल, शिवा, रामगोपाल, रोहित साहू, प्रेमलाल, सरजू साहू लोग उपस्थित थे।

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा में छह बालिकाओं का चयन

डौंडी। विगत दिनों बालोद में अंडर-17 संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बालिका फुटबॉल का आयोजन किया गया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए दुर्ग, राजनंदगांव, मानपुर - मोहला, बेमेतरा, बालोद जिला के खिलाड़ियों का

पाठक सूचना
बेमेतरा जिले में
हरिभूमि समाचार पत्र के स्थान पर कोई अन्य अखबार मिल रहा हो। एवं समाचार पत्र की प्रतियां, विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें
8319154342, 8224868411

आयोग की समझाइश पर अनावेदक अपनी पत्नी एवं बच्चों को ले जाने को हुआ तैयार दो अलग अलग प्रकरणों में किए गए सामाजिक बहिष्कार को आयोग टीम भेजकर करेगा समाप्त

हरिभूमि न्यूज | बेमेतरा

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने गुरुवार जिला बेमेतरा कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 273 वीं सुनवाई हुई। बेमेतरा जिले में कुल दूसरी जनसुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में

अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में आवेदिका को आयोग ने दी समझाइश, टेस्ट परीक्षा पास करने के बाद नियमानुसार होगी

आवेदिका ने दोनों अनावेदिकाओं के खिलाफ लिखित शिकायत अपने विभाग में किया था। जिसमें आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था। समिति ने लैंगिक उत्पीड़न का मामला नहीं होने के कारण केवल चेतावनी दिया था। उसके बाद अगस्त 2023 में आवेदिका ने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था। आयोग में सुनवाई में उपस्थित महिला संरक्षण अधिकारी ने बताया कि वह अध्यक्ष था और उनके द्वारा रिपोर्ट और अनावेदकगणों को चेतावनी दिया गया। बाद विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा आवेदिका को परेशान किया गया। आवेदिका अगर उन व्यक्तियों का नाम और पता देती है तो आयोग अगली सुनवाई रायपुर में करेगी। अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को सुना गया। प्रकरण आपसी जमीन का मामला था

जिसमें पूर्व में तहसील और न्यायालय में मामला चल चुका है। अतः प्रकरण आयोग में चलना संभव नहीं था इसलिए प्रकरण समाप्त किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसकी 15 साल की बेटी गुम हो गई थी इस वजह से आयोग में प्रकरण दर्ज कराई थी। आवेदिका ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी बेटी उन्हे मिल चुकी है। इस प्रकरण में थाना बेमेतरा ने अनावेदक के खिलाफ 363/366/(376)2 (Z) (N) और पास्को एक्ट तथा एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था जिसका निराकरण 25 नवम्बर 2023 को न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें अनावेदक को न्यायालय ने दोषमुक्त किया। निर्णय की प्रमाणित प्रति आज सुनवाई में अनावेदन लेकर उपस्थित हुआ जिसका अवलोकन कर आयोग ने न्यायालय में निर्णय हो जाने की वजह से आयोग में प्रकरण चलाया जाना संभव नहीं मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अन्य प्रकरण में आवेदिका जो शासकीय सेवा में कार्यरत है उसने अनावेदक क्रमांक 1 जो कि अनावेदक क्रमांक 3 के पति है जून 2019 में नोटरी दस्तावेज के माध्यम से विवाह करना एवं मंदिर में विवाह करना बताई अनावेदक 1 एवं 3 पति पत्नी है एवं अनावेदक 4.5 उनके संतान है उनके नाम की कृषि भूमि को अप्रैल 2019 में रजिस्ट्री के माध्यम से खरीद लिया और उसके दो माह बाद अनावेदक क्रमांक 1 से विवाह किया। स्वमेव यह प्रकरण आवेदिका के कुचेष्टा को दर्शाता है। प्रकरण काफी पेचीदा है और अंतिम निर्णय के लिए



समझाइश पर आवेदिका ने जताई सहमति

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसका पति जनपद के अधीन शाला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे जिसका सेवा के दौरान मृत्यु हो गया। आवेदिका को उनकी जगह अनुकम्पा मिल सकती है। जिनके लिए आवेदिका को डी.एड, टेस्ट परीक्षा पास करना होगा। आवेदिका ने बताया कि वह वही डी.एड. पास कर ली है एवं टेस्ट की परीक्षा दिलाने की तैयारी कर रही है। आयोग ने आवेदिका को समझाइश दी कि परीक्षा पास करने के बाद परीक्षा पास करने के बाद अनुकम्पा दिया जा सकेगा। आवेदिका ने सहमति जताई और अनावेदकगणों ने भी मदद करने की बात कही। इस प्रकरण में जिला एवं जनपद के सी.ई.ओ. को भी जोड़ा गया ताकि आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जा सके।

आगामी सुनवाई के लिए रायपुर में रखा जायेगा।

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदकगणों से समझौता हो गया है तथा आगे प्रकरण नहीं चलाना चाहती अतः आयोग ने प्रकरण समाप्त किया। अन्य प्रकरण में दोनों एक ही डिपार्टमेंट में कार्यरत थे आवेदिका ने डिपार्टमेंटल नोटिस को लेकर यह प्रकरण दर्ज की थी। वर्तमान में कार्यवाही नहीं चाहती। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण आवेदिका की शिकायत पर धारा 452/354/294/506 का अपराध दर्ज है और प्रकरण सी.जी.एम. कोर्ट में लंबित है। जिसमें अनावेदक जमानत पर है। जिसमें जिला संरक्षण अधिकारी ने भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस आधार पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया

बल लेकर जायेगी। सभी अनावेदक गण गांव मेंसाहू समाज के लोगों को एकत्र करेंगे जिसके सामने अनावेदकगण के द्वारा घोषणा किया जायेगा कि दोनों आवेदकों को सामाजिक बहिष्कार नहीं किया गया। दिनांक 15 अक्टूबर को इसकी घोषणा सामाजिक रूप से किया जायेगा। यदि अनावेदकगण ऐसा घोषणा नहीं करता है तो थाना चन्दनू में अनावेदकगण के खिलाफ एफ.आर.आई. दर्ज कराया जायेगा। इस हेतु दोनों पक्ष की ओर से एक-एक व्यक्ति को महिला आयोग रायपुर में आकर सारी प्रक्रिया कार्यवाही करना होगा। अन्य प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित दोनों पक्ष के मध्य न्यायालय से भरण-पोषण का प्रकरण निराकृत हो चुका है ऐसे में प्रकरण पर महिला आयोग में सुना जाना संभव नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अगर आवेदिका चाहती है तो महिला आयोग के वकील से अपना प्रकरण में कार्यवाही करा सकती है। अन्य प्रकरण में उभयपक्ष उपस्थित आवेदिका की पुत्री जलवन्तन का मानसिक रोग का इलाज चल रहा है। अनावेदक क्रमांक 01 आवेदिका का दमाद है और वह अपनी बच्ची व पत्नी को साथ में रखना चाहता है। उभयपक्ष को सुनने के पश्चात शेष सभी अनावेदक के खिलाफ शिकायत समाप्त किया गया। दिनांक 09 सितंबर 2024 को सखी सेक्टर/जिला कार्यालय पहुंचेगा आवेदिका भी अपनी बेटी को लेकर पहुंचेगी। अनावेदक 01 अपनी पत्नी व बच्ची को लेकर जायेगा। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

कलेक्टोरेट के 13 कर्मचारियों से ट्रेफिक पुलिस ने 6500 रुपए समन शुल्क वसूला

हरिभूमि न्यूज | बेमेतरा

संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के गेट पर बिना हेलमेट पहने जाने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। बगैर हेलमेट पहने हुए वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 13 चालकों पर

6500 समन शुल्क वसूल किया गया। कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस

अधीक्षक रामकृष्ण साहू की उपस्थिति में गुरुवार को हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेमेतरा जिले में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहन कर ही वाहन चलाने की पुनः अपील की है। कलेक्टर ने कहा है की जिला परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस के कर्मचारियों को समझाइश दे कि दोपहिया वाहन से दपतर आते-जाते समय हेलमेट का उपयोग करें। ताकि उन्हें इसकी प्रतिबन्धित आदत हो जाए और वे जब भी दोपहिया वाहन का उपयोग करेंगे तो हमेशा हेलमेट पहनकर ही



अधिकारी-कर्मचारियों को दी गई थी समझाइश

छिछले नहीं कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिले के सभी सरकारी जिला प्रमुखों को अवगत कराया था कि अपने अधिकारी-कर्मचारियों को समझाइश दी थी कि जो दोपहिया वाहन से दपतर आते-जाते हैं वे हेलमेट का उपयोग करें। ताकि उन्हें इसकी नियमित आदत हो जाए और वे जब भी दोपहिया वाहन का उपयोग करेंगे तो हमेशा हेलमेट पहनकर ही निकलेंगे। सभी विभाग के अधिकारी पहल करते तो काफी हद तक यातायात नियम का पालन होगा। आदेश भी जारी किया गया था। इसी क्रम में संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टोरेट के गेट पर बिना हेलमेट पहने जाने वाले वाहन चालकों पर नियमानुसार कार्यवाही परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा की गई।

निकलेंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने कहा। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्त शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालयों आने-जाने हेतु दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहन कर आने के आदेश भी जारी हुए थे। जिला परिवहन और यातायात पुलिस गुरुवार शाम से ही कलेक्टोरेट कार्यालय से बिना हेलमेट के वाहन चालकों को हेलमेट पहन कर वाहन चलाने की समझाइश दी। आज शुरुवार को बिना हेलमेट के वाहन से आने वाले कलेक्टोरेट के कर्मचारियों और कामकाज से आए लोगों के चालन भी काटे और समझाइश दी गई। वाहन चालक हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने : 29 अगस्त को डीएसपी कौशल्या साहू के नेतृत्व में यातायात प्रभारी उप निरीक्षक प्रवासी यादव, सडिन भलेतेनुस पन्ना एवं शेष पेज 10 पर

सीसी रोड निर्माण के लिए 17.30 लाख रुपए स्वीकृत

बेमेतरा। विधानसभा बेमेतरा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत बेमेतरा जिले के विभिन्न गांवों में विकास कार्यों के लिए 17 लाख 30 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दिपेश साहू विधायक बेमेतरा द्वारा अनुशंसित जिला बेमेतरा की अनुशंसा पर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना-अंतर्गत उक्त स्वीकृति दी है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बेरला के ग्राम पंचायत संडी में मेन रोड से प्रमोद साहू के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य लिए 4 लाख 50 हजार रुपये, ग्राम पंचायत भरचट्टी के आश्रित ग्राम तबलखोर में माते के घर से ठाकुर देव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 40 हजार रुपये, व ग्राम पंचायत भाटसोहरा में बिरजू साहू के घर से अंकलहा यादव के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख 20 हजार रुपये और विकासखण्ड एवं विधानसभा बेमेतरा के ग्राम पंचायत बीजाभाट में मनोज शर्मा के घर से दल्ली देवांगन के घर तक सीसी. रोड निर्माण कार्य के लिए 4 लाख 20 हजार रुपये, प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

एसपी कोशले ने पदभार ग्रहण किया

हरिभूमि न्यूज | बेमेतरा

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एसपी कोशले ने सहायक संचालक बेमेतरा के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले एस पी कोशले बेरला विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अछोली में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के एक पत्र तथा कलेक्टर रणबीर शर्मा के अनुमोदन के पश्चात सहायक संचालक के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। इसी के तहत आज एस पी कोशले ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर सहायक संचालक का पदभार ग्रहण कर लिया है। डाइट बेमेतरा के प्राचार्य जे के घृतलहरे ने इस अवसर पर कहा कि एस पी कोशले की गिनती पूरे जिले में एक अच्छे प्राचार्य के रूप में की जाती है। जिनमें प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ भरपूर शैक्षणिक दक्षता भी है। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे जिले के स्कूलों को और बच्चों को मिलेगा। कार्यभार ग्रहण करने के इस



अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में बेमेतरा के प्राचार्य जे के घृतलहरे, सेजेस कुसमी के प्राचार्य एस एस ठाकुर, प्राचार्य कंडरका राजेंद्र झा, नव नियुक्त एसपी द्वय भूपेंद्र साहू और धर्नजय शर्मा, डाइट बेमेतरा के प्राचार्य शिवनारायण वर्मा, सरदा के प्राचार्य लक्ष्मी नारायण गायकवाड, लेंजवारा के प्राचार्य जीवधन लाल देवांगन, सेजेस हिंदी माध्यम विद्यालय बेमेतरा के व्याख्याता प्रमोद कुमार ठाकुर, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा से व्याख्याता मनोज बक्शी, सेजेस कुसमी से व्याख्याता डॉ. कल्याण दास सहित जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के सभी स्टाफ उपस्थित थे।

सलधा के सामुदायिक शौचालय में लटक रहा ताला

बेरला। जनपद पंचायत बेरला क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत सलधा का एक मामला सामने आ रहे है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत सलधा में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। जिसमें आज भी ताला लटकता नजर आ रहे है। लोगों को खोलने में शौच जाने से रोकने के लिए दूर से चरण में प्रत्येक ग्राम में एक



सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ताकि ग्रामीण खुले

किया जा सके। लेकिन यहां पर इसके विपरीत हो रहे और ग्राम वासी खुले में शौच करने को मजबूर है। गौरतलब है कि जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत ग्राम पंचायतों का सामुदायिक शौचालय का हाल बेहाल है। कहीं पर ताला लटकता हुआ है तो कहीं सिर्फ शौ पीस बनाकर रख दिया है।

हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉ. अरुणा पल्टा शामिल हुईं

अच्छे स्वास्थ्य से होता है अच्छी मानसिकता का निर्माण : कुलपति पल्टा

हरिभूमि न्यूज | बेमेतरा

प्रेरणा विद्यालय में संचालित हायर लर्निंग कक्षा में गुरुवार को हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुईं। जहां उन्होंने अपने अनुभवों और विश्वविद्यालय के बारे में बताते हुए कहा कि 166 कॉलेज और 2 लाख बच्चे उनके विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तथा 7 जिले इससे जुड़े हुए हैं। इनमें विभिन्न कौशल और डिग्रियों से जुड़े विषय उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि वे हर कक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और जिस महाविद्यालय में वे पढ़ती थीं, वहीं से उन्होंने अध्यापन कार्य की शुरुआत की। उनकी सफलता में उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यदि दिनचर्या निश्चित हो, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और



मानसिक विकास तेजी से होता है। दिनचर्या निर्धारित करने के लिए समय का नियोजन आवश्यक होता है। रोज सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएं। प्रतिदिन योग करना और अच्छा भोजन करना आवश्यक होता है। अच्छे स्वास्थ्य से अच्छे मस्तिष्क का विकास होता है, और अच्छे मस्तिष्क से जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित होती है। प्रतिदिन एक घंटा योग करने से

आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ ही आपके मानसिक विकास में तेजी आती है और आप में प्रसन्नता बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए समय का नियोजन, समय का प्रबंधन, और कार्य करने की प्रवृत्ति इच्छा होना आवश्यक है। कोई भी कार्य समय पर करें। समय पर कार्य करने से आनंद प्राप्त होता है और प्रशंसा मिलती है, जो कि एक अद्भुत अनुभव होता है।

SAVE UNLIMITED
साड़ियाँ
20% छूट
साथ में सूटिन्ग, शर्टिन्ग, ड्रेस मटेरियल्स सलवार सूट, भैंसिन्ग, वेड शीट्स टावेल, नेपकीन आदि पर भी छूट का लाभ उठावें।
महेन्द्र कम्पनी मोदी सन्स
मालवी रोड, रायपुर (छ.ग.)
फोन: 4049406/7/8

खबर संक्षेप



वन खेलकूद स्पर्धा के लिए चयन, कई जिलों से पहुंचे खिलाड़ी

रायपुर। 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव ने स्थानीय कोटा स्टेडियम में किया। पूरे प्रदेश के 6 वन वृत्तों से आए लगभग 500 खिलाड़ियों को वन बल प्रमुख ने शपथ दिलाई। वन वृत्त बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, सरगुजा, रायपुर से आए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समस्त खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को रायपुर में होना सुनिश्चित है। उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विविध खेलों के लिए राज्य स्तरीय टीम का चयन 29 से 31 अगस्त के मध्य प्रतियोगिताएं आयोजित कर किया जा रहा है।

आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सकों के लिए पंजीयन नवीनीकरण 30 तक, फिर होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद में 30 जून 2019 तक पंजीकृत आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सकों के पंजीयन प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। परिषद के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला ने बताया कि पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि बिना विलंब शुल्क 31 अगस्त तक निर्धारित है। विलंब शुल्क के साथ 30 सितंबर तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। नवीनीकरण के लिए अभी तक 2500 चिकित्सकों के आवेदन पत्र प्राप्त हो चुका है। आवेदन पत्रों के छावनीय पश्चात अक्टूबर से चिकित्सकों को पंजीयन नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

मरीजों को दी जाएं उच्चस्तरीय सुविधाएं



रायपुर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं इससे संबद्ध डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मृति चिकित्सालय तथा डीकेएस अस्पताल की स्वशासी समिति की सामान्य परिषद की बैठक हुई। चिकित्सा महाविद्यालय के कॉलेज काउंसिल हॉल में हुई बैठक में उन्होंने मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल में मरीजों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपकरण एवं मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए। रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू और पुरेंद्र मिश्रा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. यूएस पैकरा आदि शामिल हुए।

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर अस्थाई रोक, कर्मचारी संगठनों का था भारी विरोध

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के फैसले पर सरकार ने ही अस्थायी रोक लगा दी है। एक दिन पहले इस संबंध में सचिव स्तरीय बैठक बेनतीजा रही थी। हालांकि अस्थायी रोक संबंधी आदेश की प्रति नहीं मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक व प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने रोक लगाए जाने की जानकारी मिलने की बात कही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक

एक दिन पहले इस संबंध में सचिव स्तरीय बैठक बेनतीजा रही

किरण देव ने सीएम को लिखा था पत्र

कुछ ही दिनों में नगराई निकाय और पंचायत चुनाव हैं, ऐसे में शिक्षक नेता जिस नेता के यहां ज्ञापन देने जा रहे थे, मजबूरी में ही सही उन्हें रिस्पांस देना पड़ रहा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के फैसले पर विचार किया जाए।

इन विषयों पर नहीं बनी बात

शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी से कल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और शिक्षक संगठनों से चर्चा के दौरान जोर देकर कहा था कि पहले प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक मिडिल व प्राथमरी स्कूल व शिक्षक के रिक्त सभी पदों पर हाई कोर्ट में कैबिनेट लगाकर टाइम लिमिट कर पदेनान्ति कोजिए, उन्हें रिक्त पदों पर पोस्टिंग दीजिए। विभाग द्वारा जारी 2008 के सेटअप को

यथावत रखा जावे, उससे कम पद स्कूलों में कैसे दिया जा रहा है, इसमें छेड़छाड़ गलत है। साथ ही प्रत्येक विद्यालय का स्वतंत्र यू आइस कोड हो, उनकी व्यवस्था अलग किया जा सकता है। वरिष्ठ शिक्षकों को अतिशेष न किया जाए। कामर्स, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे विषय के लिए छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक बढ़ाए जाएं। आवश्यकतानुसार नए शिक्षकों की भर्ती किया जाने की मांग की गई थी।

गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न कई शिक्षक

स्कूल शिक्षा विभाग में कई शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में लोक शिक्षण संचालनालय और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पदस्थ हैं। यहां सेटअप से अधिक लोगों की पदस्थापना की गई है। प्राचार्य और व्याख्याता स्तर के शिक्षकों को मूल पदस्थापना स्थल पर भेजने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में इसे लेकर कई शिकायतों के बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कमल वर्मा ने राज्य शासन द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने के आदेश को रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह फेडरेशन और शिक्षक के सभी संगठनों के एकता का परिणाम है। उन्होंने कहा, फेडरेशन के दबाव में शासन को अपना आदेश रद्द करना पड़ा। उन्होंने इसका स्वागत करते हुए, इसके लिए फेडरेशन और शिक्षक संगठन के लोगों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने इसे फेडरेशन की एकता का परिणाम बताते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

नवीनीकरण की तारीख नहीं बढ़ने के कारण नवीनीकरण नहीं करा पा रहे कार्डधारक

अवधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण का साफ्टवेयर ब्लॉक, 5 लाख से अधिक हितग्राहियों के कार्ड फंसे

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में अब तक 5 लाख से अधिक कार्ड धारक अपना नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं, वहीं शासन द्वारा नवीनीकरण की अवधि भी खत्म हो चुकी है, जिसके कारण नवीनीकरण का साफ्टवेयर भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके कारण राशन दुकानों में नवीनीकरण होना भी बंद हो गया है, जिससे 5 लाख से अधिक कार्ड भी फंसे गए हैं। नवीनीकरण नहीं होने से नये कार्ड भी नहीं बन पाएंगे, जिससे आगामी दिनों में हितग्राहियों को राशन से भी वंचित होना पड़ सकता है। इधर जिला विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नवीनीकरण कराने के लिए कार्ड धारकों को भरपूर समय दिया गया है। इसके लिए कई बार अवधि भी बढ़ाई गई, बावजूद नवीनीकरण कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में धारकों का नवीनीकरण नहीं हो पाया है, इसे देखते हुए अवधि बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।



नवीनीकरण नहीं कराने वालों में 80% एपीएल कार्ड धारक
नवीनीकरण नहीं कराने वालों में ज्यादातर एपीएल कार्ड धारक बताए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेशभर में जितने कार्ड अब तक नवीनीकरण नहीं हो पाए हैं, उनमें लगभग 80 प्रतिशत एपीएल कार्ड धारक हैं। रायपुर जिले की बात करें तो यहां भी 70 हजार से अधिक कार्ड धारकों ने नवीनीकरण नहीं कराया है। इनमें 50 हजार से ज्यादा एपीएल कार्ड धारक हैं।

किए जा रहे हैं। इस तरह नवीनीकरण कराने के बाद ही नये कार्ड बनाए जा रहे हैं। आगामी दिनों में नये कार्ड वाले धारकों को ही राशन दुकान से खाद्यान्न मिलना है।

76 लाख से अधिक कार्ड, 93% करा चुके नवीनीकरण
प्रदेशभर में कार्ड धारकों की संख्या 76 लाख 65 हजार 523 हैं। इनमें से 71 लाख 26

15 अगस्त के बाद नहीं हो रहा नवीनीकरण, चक्कर लगा रहे धारक

शासन के निर्देश के अनुसार 15 अगस्त को नवीनीकरण कराने की अंतिम तारीख तय की गई थी। इसके बाद से नवीनीकरण का काम बंद है। इधर नवीनीकरण का काम बंद होने के बाद अब राशन दुकानों में कार्ड धारक नवीनीकरण के लिए चक्कर काट रहे हैं। रायपुर शहर के कुछ दुकान संचालकों ने बताया कि हर रोज दो से तीन लोग नवीनीकरण कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन साफ्टवेयर बंद होने के कारण वे नवीनीकरण नहीं कर पा रहे हैं।

नवीनीकरण की अंतिम बार तारीख बढ़ाने मेजा है प्रस्ताव

जिले में अब तक करीब 11 प्रतिशत कार्ड धारकों ने नवीनीकरण नहीं कराया है। 15 अगस्त तक का समय दिया गया था। इसके बाद साफ्टवेयर ब्लॉक कर दिया गया है। नवीनीकरण की तारीख अंतिम बार आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
- भूपेंद्र मिश्रा
जिला खाद्य निबंधक

तोखन झारखंड की चार विधानसभाओं के प्रभारी

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू को चार विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया है। रांची में शुक्रवार को होने वाली भाजपा की वे बैठक के लिए गुरुवार को वे बिलासपुर से रांची के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले हरिभूमि से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा, राष्ट्रीय संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने प्रभारी वाली सीटों के साथ ही झारखंड में भाजपा को जीत दिलाने के लिए काम करूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग राज्यों के सांसदों, और भाजपा नेताओं को जिम्मा सौंपा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को झारखंड में लातेहार और चतरा जिले की चार विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया है। इन जिलों में लातेहार, चंदवा, चतरा और सिमरिया सीटें हैं। इस समय लातेहार सीट पर जेएमएम और चंदवा सीट पर कांग्रेस, चतरा की सीट में राजद और सिमरिया की सीट पर भाजपा के विधायक हैं। अब चारों सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने का जिम्मा श्री साहू के पास है। इसके लिए वे वहां पर रणनीति बनाने का काम करेंगे और भाजपा नेताओं के साथ जीत के लिए काम करेंगे।

पेज 9 का शेष कलेक्टोरेट के 13 कर्मचारियों...

अन्य स्टाफ के द्वारा संयुक्त कार्यालय बेमेतरा के सामने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन चेकिंग किया गया। जिसमें दोपहिया वाहन चालक अधिकारी-कर्मचारी जो दफ्तर आते-जाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने पाये जाने पर हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को बताकर समझाईश दिया गया साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना हेलमेट धारण किये 13 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। जिसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के विरुद्ध 13 प्रकरण में कुल 6,500 रुपए समन शुल्क लिया गया।

वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने दी समझाईश: बेमेतरा पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाए, मालवाहक वाहन में सवारी न बैठाएं, अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावें। और वाहन चालकों को बताया कि वाहन में नंबर नहीं लिखें होने पर समन शुल्क लिया जाता है। इसलिए बिना नंबर के वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करने की जानकारी दी। बेमेतरा पुलिस आपकी सहायता के लिए है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

भाजपा ने सदस्यता के लिए झोंकी ताकत, 50 हजार प्रभारी सीधे वार रूम के टच में रहेंगे

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

प्रदेश भाजपा संगठन ने सदस्यता अभियान के लिए बड़ी ताकत झोंकने का फैसला किया है। बूथों से लेकर मंडल, शक्ति केंद्र, जिलों में प्रभारी बनाए गए हैं। करीब 50 हजार प्रभारियों को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बनाए गए वार रूम से सीधा जोड़ा जा रहा है। वार रूम में रोज का डाटा भी अपडेट होगा। प्रभारियों के साथ किसी भी कार्यकर्ता को सदस्य बनाने में किसी भी तरह से परेशानी होगी, तो उनको वार रूम से मदद मिलेगी। वार रूम में एक काल सेंटर बनाया गया है। इसमें कार्यालयीन समय में एक से डेढ़ दर्जन जानकार कॉल अटेंड करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। भाजपा का लक्ष्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का है।

भाजपा का सदस्य अभियान प्रदेश में तीन सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पहला सदस्य बनाकर प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद चार सितंबर को जिलों में प्रदेश के मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी अभियान का आगाज करेंगे। पांच सितंबर को मंडलों में और अंत में 6 सितंबर को बूथों से अभियान प्रारंभ होगा। सदस्य बनाने का काम बूथ स्तर से होगा। ऐसे में सदस्यता अभियान का सही में प्रारंभ 6 सितंबर से होगा। हर बूथ में कम से कम दो सौ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।



हर स्तर पर प्रभारी तय

भाजपा का सबसे बड़ा फोकस बूथ पर है। ऐसे में प्रदेश के 25 हजार बूथों में बूथ प्रभारी बनाए गए हैं। इसी के साथ चार हजार से ज्यादा शक्ति केंद्र, चार सौ से ज्यादा मंडलों के अलावा जिलों में भी प्रभारी और उक्त सहायक बनाए गए हैं। सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अजय सिंहदेव के सुताधिक कुल मिलाकर करीब 50 हजार प्रभारियों को सदस्यता का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश संगठन से जुड़े जिलों, मोर्चा, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और सदस्य भी सदस्यता अभियान में काम करेंगे। लेकिन ठाकरे परिसर के वार रूम में प्रभारियों का डाटा रहेगा। उनके नंबरों को वार रूम में रखने का काम चल रहा है। वार रूम 6 सितंबर से काम करेगा।

सबकी जिम्मेदारी तय

सदस्यता अभियान के लिए सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। एक दिन पहले सभी मोर्चा की बैठक लेकर प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने मोर्चा के पदाधिकारियों को बताया कि सदस्यता अभियान के लिए क्या करना है। गुरुवार को सभी प्रकोष्ठ की बैठक

ली गई। इसमें सदस्यता अभियान को लेकर सभी को भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और सदस्यता अभियान के संयोजक अनुराग सिंहदेव ने पूरी जानकारी दी और बताया कि क्या-क्या करना है।

मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन संग्रहालय का लिया जायजा

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को नवा रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के समीप बन रहे 'शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय' का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित इस संग्रहालय का निर्माण 45 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम भी कार्य की प्रगति देखने पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय ने संग्रहालय में मूर्तियों, अन्य कलाकृतियों तथा विभिन्न मॉडलों का अवलोकन



किया। उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कर रहे शिल्पकारों से चर्चा कर उनकी कला के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि ट्रायबल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के जनजातीय गौरव का एक प्रमुख केन्द्र बनेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के देश प्रेम की

भावना, उनके शौर्य पराक्रम और बलिदानों पर केन्द्रित यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को सहेजने का अनुपम प्रयास है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को संग्रहालय के कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को सौंपा ज्ञापन

भूपेश के काफिले को रोकने और दुर्यवहार की उच्च स्तरीय जांच की मांग

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हमले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर कांग्रेसी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर डीजीपी के न होने पर कांग्रेस के नेताओं ने वहां के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घेरा गया है कि 24 अगस्त को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोका और सुरक्षा कर्मियों से धक्का-मुक्की की गई। घटना के विरोध में भिलाई-3 थाने में घेरा गया है। शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और एफआईआर की गई। प्रतिनिधिमंडल में शहर अध्यक्ष गिरिशी दुबे, एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय, प्रमाद दुबे, पंकज शर्मा, महेंद्र छाबड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है, इस सुरक्षा में चूक पुलिस प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा, दुर्ग में प्रदर्शन करने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने व उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की बजरंग दल ने क्या कोई परमिशन ली थी? उनके काफिले को सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज एवं एफआईआर करना अलोकतांत्रिक



दर्शाता है। उन्होंने कहा, दुर्ग में प्रदर्शन करने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने व उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की बजरंग दल ने क्या कोई परमिशन ली थी? उनके काफिले को सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज एवं एफआईआर करना अलोकतांत्रिक

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री का पुतला फूँका

भिलाई में स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई लाठीचार्ज व 150 से अधिक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री व गृहमंत्री का पुतला जलाया। कांग्रेस भवन गांधी मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष गिरिशी दुबे के नेतृत्व में पुतला जलाया। शहर अध्यक्ष गिरिशी दुबे ने कहा, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में असामाजिक तत्वों ने धरे कर उनके साथ दुर्यवहार किया। पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, तो छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज एवं एफआईआर करना अलोकतांत्रिक



व्यवस्था को दक्षता है। साय की सरकार तानाशाही रचये में उतर चुकी है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस तानाशाही सरकार से हर मोर्चे पर लड़ता रहेगा। ये थे मौजूद - इस दौरान धर्या वर्मा, उषामा वर्मा, कन्हैया अग्रवाल, आकाश शर्मा, प्रशांत ठेंगडी, नवीन चंद्रकार, दीपा बगना, देव कुमार साहू, माधव साहू, दिनेश ठाकुर, बाकर अब्बास, जी. श्रीनिवास, बंधी कञ्जोले, ममता राय आदि उपस्थित थे।



खबर संक्षेप

सिग्नल टाइमर शुरू करने की मांग, सौंपा ज्ञापन

रायपुर। राजधानी के अधिकांश चौक-चौराहों पर बंद पड़े सिग्नल टाइमर को शुरू करने की मांग को लेकर शिवसना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कामगार सेना प्रदेश उपाध्यक्ष बल्लू जांगड़े ने बताया कि शहर के व्यस्ततम चौक पर लगे सिग्नल टाइमर बंद होने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं से पूर्व अनुमान लगाकर सड़क पार करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है और साथ ही चालानी कार्रवाई के दायरे में आ जाते हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में एचएन सिंह पालीवार, संतोष मारकंडे, आनंद तिवारी, मोहित सिन्हा, हरीश साहू आदि शिवसैनिक शामिल हुए।

गांडा महासभा ने राजेश दीप की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

रायपुर। गांडा महासभा के पदाधिकारियों ने गुरुवार को गांडा महासभा के पूर्व अध्यक्ष राजेश दीप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान गांडा महासभा परिवार ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दो मिन्ट का मौन धारण किया। साथ ही कहा कि समाजहित में दिए गए योगदान के लिए समाज हमेशा स्व. राजेश दीप का ऋणी रहेगा और हमेशा उनको स्मरण करेगा। संयोजक रघुचंद निहाल ने कहा, राजेश दीपजी गांडा समाज के प्रमुख स्तंभ थे। श्रद्धांजलि देने वालों में नारायण बाग, कमने सोना, बसंत बाग, राजमोहन बाग, डमरुधर दीप, सुरेंद्र बघेल, बंटी निहाल, पृथ्वी महानंद, मंगल छत्री, आनंद नायक, हीराधर सोनी समेत महासभा परिवार के अनेक सदस्य उपस्थित थे।

राज्यपाल ने राजभवन कर्मियों के निधन पर दी श्रद्धांजलि

रायपुर। राज्यपाल रमन डेका ने राजभवन सचिवालय में कार्यरत टेलीफोन ऑपरेटर राजेश सुधाकर के आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों ने शोकसभा आयोजित कर मृतात्मा की शांति के लिए 2 मिन्ट का मौन रखा।

हीरापुर बाजार और विसर्जन कुंड के पास बनेगा वॉडिंग जोन

रायपुर। शहर में फुटकर विक्रेताओं को व्यवस्थित रूप से आजीविका चलाने नगर निगम जोनवार वॉडिंग जोन विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जोन 8 वॉडिंग कमेटी की बैठक महाबा बाजार स्थित जोन कार्यालय में हुई। इसमें 2 जगहों पर नए वॉडिंग जोन बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। ये नए वॉडिंग जोन हीरापुर बाजार और रायपुरा क्षेत्र में विसर्जन कुंड के पास विकसित किये जायेंगे। नगर निगम के जोन 8 कार्यालय में टेंडर वॉडिंग कमेटी की बैठक जोन अध्यक्ष धनश्याम छत्री, एमआईसी सदस्य श्रीकुमार मेनन, जोन कमिश्नर एके हलदार, एनयूएलएम की मिशन प्रबंधक सुषमा मिश्रा और पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित वेंडर्स की उपस्थिति में हुई।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील बोरो जिला दुर्ग (छ.ग.)
॥ इंतजार ॥
रा.प्र.क्र.-202407104400018
अन-74 / वर्ष 2023-24
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनायें प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक जीवन पटेल पिता हिन्धाराम पटेल साकिन देउकोना तहसील बोरो जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा ग्राम देउराकोना प.ह.नं.-01 राजस्व निरीक्षक मण्डल बोरोजुगुं तहसील बोरो स्थित भूमिधर्म हक में दर्ज भूमि खसरा नंबर 340/3, 468/3, 598, रकबा 0.36, 0.07, 0.34 हे. कुल खसरा नंबर 03 कुल रकबा 0.77 हे. जीवन पटेल पिता हिन्धाराम अन्य-03 के नाम पर राजस्व अधिलेख दर्ज है, का द्वितीय प्रति प्रश्न पुलिसका प्रदाय किये जाने बाबत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण इस न्यायालय में विचारधीन है।
अतः द्वितीय प्रति प्रश्न पुलिसका प्रदाय किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति/बाधा हो तो वे नियत समय में स्वयं अथवा अपने मान्य अधिकारताएण के साथ सुनवाई दिनांक 09.09.2024 को या उसके पूर्व उपस्थित होकर अपने आपत्ति/बाधा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।
मुख्य न्यायालय तहसीलदार बोरो

हाइब्रिड वनभैसों के लिए दस साल में फूँके ढाई करोड़, अब चारे के लिए पैसा नहीं

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर
राज्य के राजकीय पशु वनभैसों की जतन के लिए वन विभाग पिछले दो दशक से मशकत कर रहा है। राजकीय पशु के लिए विभाग ने अब तक जो कुछ भी किया है, वह विवादों में रहा है। उदती में वनभैसा रेस्क्यू सेंटर में रखे गए वनभैसों के हाइब्रिड होने के बाद सीजेडए ने उन वनभैसों का क्रॉस कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद विभागीय अफसरों ने पिछले वर्ष जुलाई में 16 हाइब्रिड वनभैसों को खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़े जाने पर हाइब्रिड वनभैसों किसानों की फसल चट करने लगे। इसके बाद

हाइब्रिड वनभैसों को लेकर वन विभाग असमंजस की स्थिति में
डिप्टी डायरेक्टर ने सीडीब्लूएलडब्लू को दिए सुझाव
वनभैसों को लेकर उदती-सीतलदीह टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर करुण जैन ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुधीर अग्रवाल को पत्र के माध्यम से सुझाव दिया है। सुझाव में इन हाइब्रिड वन भैसों को ग्रामीणों के हाथों सौंपने या फिर उन्हें रूस्टीआर के क्षेत्र से बाहर छोड़ने की बात का उल्लेख है। पत्र में अफसर ने कहा है कि इन्हें सारे हाइब्रिड वनभैसों के लिए चारा नहीं है। इस वजह से एनिमल आक्रमक हो सकते हैं या भूख से मर सकते हैं। हाइब्रिड वनभैसों का व्यवहार पालतू मवेशी की तरह है।
■ खुले में छोड़ने पर किसानों ने हकाल कर वापस बाड़े में लौटाया



पीडित किसानों ने खुले में विचरण कर रहे हाइब्रिड राजकीय पशु को हकाल कर पुनः बाड़े में बंद कर दिया है। गौरतलब है कि वन अफसर इन हाइब्रिड वनभैसों के खाना तथा अन्य देख रेख में वर्ष 2013 से वर्ष 2024 के बीच अब तक दो करोड़ 46 लाख 38 हजार 831 रुपए खर्च कर चुके हैं। वर्तमान में इन एनिमल के लिए चारा तथा देख-रेख करने विभाग के पास फंड नहीं है।

मामला सुलझाने समिति का गठन

खुले में हाइब्रिड वनभैसों को छोड़ने के बाद किसानों को फसल नुकसान करने के मामले को सुलझाने तथा किसानों को क्षतिपूर्ति देना पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के समिति गठित की है। जानकारों के मुताबिक मामला विभागीय की जगह सरकार के स्तर पर सुलझाया जाना है।

किसानों से पकड़े और खरीदे गए थे
जिन एनिमल के हाइब्रिड वनभैसा होने की पुष्टि हुई है, उनमें से एक मादा एनिमल को वर्ष 2008 में एक किसान से यह कहकर लाया गया कि यह भूरा की जगह वनभैसा है। इसके बाद बाड़े में रह रहे प्योर नस्ल के छोटू के साथ उसका क्रॉस कराया गया। किसान से लाए गए कथित वनभैसा का नाम अफसरों ने आशा रखा। आशा ने राजा, प्रिंस, मोहन, वीरा, सोमू, खुशी और हीरा को जन्म दिया। आशा की 2020 में मृत्यु हो गई। इसके बाद वन अफसरों ने वर्ष 2018 में किसानों से 27 हजार रुपए में दो और हाइब्रिड वनभैसा खरीदा, जिनका नाम रमा तथा मेनका रखा। रमा तथा मेनका से जन्मे हाइब्रिड वनभैसों मालती और मानुमति को जन्म दिया। चारों ने पार्वती, विष्णु, दुर्गा, किरण, कान्हा, प्रहलाद, रवि, सोमवती, जानकी, उर्वशी और सूर्या को जन्म दिया। इस तरह से रेस्क्यू सेंटर में हाइब्रिड वनभैसों की संख्या में वृद्धि होती गई।

शराब दुकानों का ठेका लेने वाली एजेंसियों के विरुद्ध प्रदेशभर के सुरक्षा गार्डों ने खोला मोर्चा

12 घंटे की ड्यूटी, वेतन आधे से कम, पीएफ-छुट्टी भी नहीं, शराब दुकानों के सुरक्षा गार्ड हड़ताल की तैयारी में

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर
शासकीय शराब दुकानों की सुरक्षा का ठेका लेने वाली एजेंसियों के खिलाफ प्रदेशभर के सुरक्षा गार्डों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी जिलों से सुरक्षा गार्ड अपनी मांगों को लेकर राजधानी पहुंचे थे, यहां वे जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित होने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री से मिले बिना ही लौटना पड़ा। सुरक्षा गार्डों ने हरिभूमि से बातचीत करते हुए बताया कि सीएसएमसीएल द्वारा सुरक्षा गार्डों का वेतन निर्धारित किया गया है। इसके तहत उन्हें वेतन आधे से भी कम दिया जा रहा है, वहीं 8 की जगह 12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है, लेकिन ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही भविष्य निधि का पैसा भी नियमित रूप से जमा नहीं किया जा रहा है।
ओवर टाइम का वेतन देने से एजेंसियों का इंकार
सुरक्षा गार्डों ने बताया कि मासिक वेतन आदेश जारी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 12 घंटे की जगह अब 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से उनका वेतन दिया जा रहा है, जबकि वर्ष 2017 से लेकर अप्रैल 2024 तक सभी गार्डों से 12 घंटे की ड्यूटी कराई गई है। वेतन आदेश जारी होने के बाद एजेंसियों अब ओवर टाइम का वेतन देने से पीछे हट गई हैं।

जनदर्शन कार्यक्रम में देना चाहते थे सीएम को ज्ञापन

इन एजेंसियों से हुआ है अनुबंध
आबकारी विभाग ने विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों से अनुबंध किया है। इनमें एसआईएस, बीआईएस, इगल हंटर, सीएसएमसीएल, कॉलमी, एसएसएस आदि एजेंसी शामिल है।
22861 वेतन निर्धारित पर एजेंसियां 6 से 12 हजार ही दे रही हैं
सुरक्षा गार्डों ने बताया कि शराब दुकानों की सुरक्षा के लिए आबकारी विभाग ने प्रदेशभर में आधा दर्जन से अधिक एजेंसियों से अनुबंध किया है। इस अनुबंध के तहत सीएसएमसीएल द्वारा सुरक्षा गार्डों को एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाला वेतन एवं सुरक्षा निधि भी निर्धारित किया गया है। इस आदेश के तहत 8 घंटे की ड्यूटी, मानदेय राशि 10620, ओवर टाइम चार्ज 402 रुपए, छुट्टी चार्ज 408 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन का 1633 रुपए। इस तरह कुल 22861 रुपए मासिक वेतन दिया जाना है। सुरक्षा गार्डों ने बताया कि अनुबंध की तुलना में उन्हें न ही निर्धारित वेतन दिया जा रहा है और न भविष्य निधि जमा की जा रही है। ड्यूटी की 8 की जगह 12 घंटे कराई जा रही है। छुट्टी मांगने पर वेतन काटने या नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। उन्होंने बताया कि एजेंसियों द्वारा मनमाने तरीके से वेतन दिया जा रहा है। कोई एजेंसी 6 हजार, कोई 7 से 8 तो कोई 9, 10 से 12 हजार वेतन दे रही है।

कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे

कबीरधाम, दंतवाड़ा, बीजापुर, मुंगेली, अंबिकापुर, कोरबा, रायपुर, दुर्ग-भिलाई, धमतरी, कांकेर सहित सभी जिलों से सुरक्षा गार्डों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर उनके द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस मामले में एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। थककरकरकर अब वे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि आगामी जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वे देबारा आएंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद भी अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

35 किलो पारसल विदेश भेजने में कस्टम ड्यूटी से राहत, उद्यमियों की नई उड़ान से बड़ी बुकिंग

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर
छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को सात समंदर पर व्यावसायिक पारसल पहुंचाने के लिए अब बिचौलियों को मोटी रकम देने से राहत मिल रही है। ऐसे ग्राहकों के लिए डाक विभाग ने रायपुर डिपोजिट में आज हाह डाक निर्यात केन्द्र शुरू किया है। इसको वन पाईट सॉल्यूशन कहा जाता है, जहां से लोग विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को ही नहीं, बल्कि उद्यमी 35 किलो वजन अपने प्रोडक्ट को भी कस्टम ड्यूटी के पेंच में फंसे बिना आसानी से बुकिंग करवा रहे हैं। डाक विभाग अब हर वर्ग को काउंटर से जोड़ने के लिए प्रयोग कर रहा है। इसका फायदा उद्यमी व व्यापारी भी लेने लगे हैं। जुलाई से पहले विदेशों के लिए व्यावसायिक पारसल भेजने के लिए व्यापारियों को लाइन लगानी होती थी। बुकिंग का समय सीमित होने से कई बार उन्हें लौटना पड़ता था।

खाली प्लाट में नियम विपरीत टैक्स, वार्डों के विकास कार्य ठप होने से एमआईसी सदस्य व जोन अध्यक्ष नाराज

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर
मेयर इन काउंसिल के सदस्यों और जोन अध्यक्षों ने शहर में खाली प्लॉट पर नियम विपरीत अनाप-शनाप टैक्स वसूलने का विरोध किया है। सभापति प्रमोद दुबे, वरिष्ठ एमआईसी सदस्य ज्ञानेश शर्मा श्रीकुमार मेनन, नागभूषण राव, समीर अख्तर, जितेन्द्र अग्रवाल, रिशेरा त्रिपाठी, सुरेश चन्नावार सहित अन्य सदस्यों ने गुरुवार को इस संबंध में निगम आयुक्त अंबिनाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। एमआईसी सदस्यों ने निगम आयुक्त पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव में आकर वे वार्डों के विकास कार्य की अनदेखी कर रहे हैं। इससे शहर के 70 वार्डों में विकास कार्य ठप पड़ा है। वरिष्ठ एमआईसी सदस्य श्रीकुमार मेनन, सभापति प्रमोद तत्काल प्रारंभ करवाया जाये।
■ गांधी सदन में निगम आयुक्त अंबिनाश मिश्रा को सौंपा ज्ञापन
■ राजनीतिक दबाव में काम करने का लगाया आरोप
दुबे ने कहा है कि नगर निगम रायपुर के 70 वार्डों में विकास कार्य प्रभावित हैं। सामान्य सभा और एमआईसी की बैठक में हुई चर्चा व इस संबंध में लिये गये निर्णय के बावजूद अब तक कोई प्रगति व कार्यवाही प्रशासनिक स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। यही नहीं, जिन कार्यों का टेंडर हो चुका है उसे तत्काल प्रारंभ करवाया जाये।

ज्ञापन के प्रमुख बिंदु इस तरह

- 0 खाली प्लॉट में नियम विपरीत लगाये जा रहे अनाप-शनाप कर वसूली पर रोक लगाई जाये। सर्वदलीय पार्षदों की बैठक बुलाकर इसमें यथोचित ठोस निर्णय लिया जाये।
- 0 प्रत्येक वार्ड के लिए 50-50 लाख रुपये के विकास कार्य तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान कर निविदा की कार्यवाही की जाये।
- 0 सामान्य सभा व एमआईसी में हुये निर्णय के तहत वार्ड के राजस्व वसूली के 15 फीसदी तक की राशि के विकास कार्य के प्रस्ताव पर तत्काल स्वीकृति प्रदान करें।
- 0 इस सत्र के पार्षद निधि के कार्य की निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही की जाये।
- 0 सभी विभागों की विभागीय समीक्षा बैठक महापौर, समापति, आयुक्त व एमआईसी सदस्यों की उपस्थिति में 7 दिन के अंदर बुलाने की मांग।
- 0 निविदा हो चुके कार्यों को तत्काल प्रारंभ करवाया जाये।

बुजुर्ग माता-पिता ने लगाई न्याय की गुहार, बेटे ने नहीं दिया मकान व प्लाट का पैसा

रायपुर। काली नगर में 65 वर्षीय बेटी कुंजलता देवांगन के पास रहने वाले 95 वर्षीय बरतू राम देवांगन 90 वर्षीय पत्नी कुंवर बाई के साथ व्याय को गुहार लगाने के लिए गुरुवार को मोर्ता बाग स्थित प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुचुड़ में मकान व जमीन को बेचते समय जो पैसा मिला, उसे बेटे ने खुद रख लिया। पालन-पोषण नहीं होने से विगत 32 साल से बेटी कुंजलता देवांगन पति-स्व. धनेश देवांगन के काली नगर पट्टरी स्थित मकान में रहता हूं। मेरा खर्च वहन करने की स्थिति में पेशन के अंशों पर चलाने वाली बेटी भी नहीं है। इसे देखे हुए थाने और महिला आयोग में व्याय के लिए पक्कर लगाने का साहस भी नहीं रहा है। वहां से सूचना मिलने के बाद भी बेटा खुदाई में आने के कर गार्ड निकालनी थी, पर तालाब में डेयरी के मवेशियों के गोबर और गाद भारी मात्रा में जमा होने से गहरीकरण के लिए देगुना खुदाई करानी पड़ी। इसी तरह बघवा तालाब का पहले प्रस्तावित एरिया 4.5 एकड़ मानते हुए गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का इस्टीमेट तैयार किया गया, पर तालाब का सीमांकन कराने के बाद आधा एकड़ एरिया बढ़ गया।

लाखों का टैक्स बकाया निगम ने पांच बकायादारों की दुकानों पर लगाया ताला

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर
नगर निगम जोन-3 राजस्व विभाग की टीम ने गुरुवार को बकाया टैक्स वसूली अभियान चलाया, जिसमें लालबहादुर शास्त्री वार्ड के 4 बकायादारों द्वारा बकाया टैक्स भुगतान नहीं किए जाने पर उनकी दुकानें सील की गईं। इसी तरह मदर टेरेसा वार्ड के एक बकायादार की दुकान को सील किया गया। नगर निगम आयुक्त अंबिनाश मिश्रा के आदेश और अपर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर जोन-3 के राजस्व विभाग ने जोन कमिश्नर जसदेव सिंह बांबरा के निर्देश पर बकाया

राजस्व वसूली अभियान चलाया, जि स में लालबहादुर शास्त्री वार्ड की नाजिया बानो की बकाया राशि 1 लाख 45 हजार 764 रुपए, आरती बेर्जे की 1 लाख 27 हजार 589 रुपए, रीना वार्ड 2 लाख 49 हजार 762 रुपए का बकाया राजस्व भुगतान नहीं होने पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई। इसी तरह मदर टेरेसा वार्ड के अंतर्गत हरीश बी. रंगलानी के 4 लाख 12 हजार 602 रुपए बकाया राशि जमा नहीं करने पर दुकान सील की गई। राजस्व अमले ने रानी लक्ष्मीबाई वार्ड अंतर्गत विजय पांडे अमन नगर मोवा में 9 हजार 66,849 रुपए, सुमित्रा शर्मा 3 लाख 33 हजार 903 रुपए, कुमुद कुर् 2 लाख 69 हजार 553 रुपए और कालीमाता वार्ड के करदाता मनमोहन से राजीव नगर क्षेत्र में 72 हजार 163 रुपए, ऋषिराज रंगलानी 1 लाख 82 हजार 801 रुपए, दिलीप हरि रम्मानो 17 हजार 322 और श्याम गोविंद दांडेकर को डिमांड बिल तामील करते ही बकाया राशि भुगतान किया गया।

बघवा तालाब, पहाड़ी तालाब सौंदर्यीकरण का आधे में रुका काम, फंड की कमी, प्रस्ताव भेजेंगे

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर
रायपुरा के बघवा तालाब और कुशालपुर के पहाड़ी तालाब गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम फंड की कमी से आधे में रुक गया है। अधूरे काम को पूरा करने नगर निगम अब अतिरिक्त फंड के लिए प्रस्ताव भेजेगा। वहीं निकाय चुनाव से पहले इन तालाबों के उद्घाटन की तैयारी शुरू हो गई है, जबकि बघवा तालाब में पेंवर लगाने, लैंडस्केपिंग, पौधापोषण से लेकर योग रूम बनाने और सौंदर्यीकरण सिटीजन रूम बनवाने का काम होना बाकी है। शहर के 2 प्रमुख तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम कराने

पैसे कम पड़ गये। माधवराव सप्रे वाई स्थित रायपुरा के बघवा तालाब को दो दशक बाद गहरीकरण और सौंदर्यीकरण कराने नगर निगम को सुध आई। अधिकारियों ने 2.53 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर इस कार्य को पूरा कराने टेंडर किया। योजना को मुताबिक तालाब को 3 फीट गहराई तक खुदाई कर गाद निकालनी थी, पर तालाब में डेयरी के मवेशियों के गोबर और गाद भारी मात्रा में जमा होने से गहरीकरण के लिए देगुना खुदाई करानी पड़ी। इसी तरह बघवा तालाब का पहले प्रस्तावित एरिया 4.5 एकड़ मानते हुए गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का इस्टीमेट तैयार किया गया, पर तालाब का सीमांकन कराने के बाद आधा एकड़ एरिया बढ़ गया।

नगर निगम को किराया की नई नीति का इंतजार, एक साल से प्रस्ताव लंबित

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर
नगर निगम को शहर में अपनी दुकानों के नई किराया नीति का इंतजार है। 1 साल पहले नई किराया नीति तय करने महापौर एजाज डेबर की परिश्रम ने एमआईसी में प्रस्ताव पारित सामान्य सभा में इसकी मंजूरी मिलने के बाद राज्य शासन के पास भेजा था। नई किराया नीति शासन स्तर पर लंबित है। ऐसे में अब नई

रूप में मिलते हैं, जो कि बाजार के लोकेशन व दर के हिसाब से बेहद बहुत कम है। इसीलिए शहरी सरकार ने लाइसेंसों हक में सालों पहले आर्वाटिड अपनी दुकानों को किराये पर देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पूर्व में नई किराया नीति तय करने शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया। इसकी मंजूरी मिलते ही इन दुकानों की नई किराया दर लागू होगी।

शहर के 10 लोकेशन में निगम की 1822 दुकानें, सालभर का किराया महज 58 लाख

सरकार नगर निगम की दुकानों की किराया नीति तय करेगी। रायपुर नगर निगम की शहर में 10 स्थानों पर करीबन 1822 दुकानें लाइसेंसों हक में सालों पहले आर्वाटिडियों को दी गई है। इनसे नगर निगम को एक साल में मात्र 58 लाख रुपये किराये

Health Town
K'sagar's
श्री श्रेयन आयुर्वेद
Panchkarma & Wellness Centre
(संतुलन से भरा आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन का राज)
वैद्य-डॉ. पल्लवी क्षीरसागर
MD आयुर्वेद (पुणे) Mob: 9111922122, 9111912122, 0771-3558564
Timing- (11-8) by Appointment पता :- B-22, जगन्नाथ मंदिर के पीछे, गायत्री नगर, रायपुर (छ.ग.)
विज्ञापन हेतु संपर्क करें: 0771- 4242213, 7987119756, 9303508130

